कृषि संकट : किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- शेर सिंह सांगवान (प्रोफेसर, सेंटर फॉर रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़)

17 जनवरी, 2019

"मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) - आधारित सरकारी खरीद प्रणाली आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि फसल उत्पादन के बाजार बुद्धिमत्ता-आधारित विनियमन (मार्केट इंटेलिजेंस-बेस्ड रेगुलेशन) पर विचार किया जाये।"

किसान हमेशा ही संकट में रहते हैं जब उनकी उत्पादन की कीमतें कम होती हैं। स्पष्ट रूप से राजनीतिक दबावों से प्रेरित सरकारों की प्रतिक्रिया, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में तेजी से बढ़ोत्तरी या ऋण माफी की घोषणा करने के लिए रही है।

इस प्रकार, केंद्र में वर्तमान सरकार ने खरीफ और रबी दोनों फसलों के एमएसपी को 2018-19 के लिए महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है और यह दावा किया है कि सरकार ने 2014 के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है, जहाँ इन्होंने किसानों की अनुमानित उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना मुनाफा अदा करने का वादा किया था। राज्य सरकारों, चाहे भाजपा की हों या विपक्ष की, ने कर्जमाफी के पैकेजों का अनावरण किया है। तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा जैसे कुछ किसानों ने प्रति एकड़ या प्रति परिवार/घरेलू आधार पर, किसानों को वार्षिक सहायता की घोषणा की है।

हालांकि, वास्तव में कृषि संकट के समाधान के संबंध में इन त्वरित-समाधानों में से कोई भी जमीनी स्तर पर कार्य करने में सफल नहीं हो सका है। भले ही उनके पास तेलंगाना द्वारा लायी गयी रायथू बंधु (किसानों का मित्र) प्रति एकड़ सहायता जैसी योजना हो, लेकिन राजकोषीय लागत उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बनाती है। दूसरी ओर, एमएसपी और ऋण माफी, संभवत: अभी तक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं।

इसके अलावा, ऐसी कई रिपोर्टें हैं जो यह दर्शाती हैं कि अधिकांश फसलों के बाजार मूल्य नवीनतम एमएसपी के नीचे कमजोर साबित हो रहे है। गन्ने के मौजूदा 2018-19 सीजन में, यदि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा निर्धारित उच्च सलाह दरों को छोड़ दिया जाए तो, मिलर्स उत्पादकों को केंद्र की उचित और पारिश्रमिक कीमत का भुगतान करने में भी संघर्ष कर पड़ रही है।

उपरोक्त कृषि संकट और पर्याप्त रूप से इसे कम करने की अक्षमता पूरी तरह से कीमतों के साथ जुड़ी है। उच्च एमएसपी का अर्थ बहुत कम है, जब बाजार की आपूर्ति और मांग की स्थिति और सरकारी खरीद की कमी उनके प्रभावी प्रवर्तन की अनुमति नहीं देती है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) धान और गेहूं की खरीद का काम करता है, जिसमें 2017-18 में क्रमश: दो अनाज का उत्पादन 33.8 प्रतिशत और 35.90 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जैसी एजेंसियों के माध्यम से दाल और तिलहन की खरीद के साथ-साथ केंद्र की मूल्य समर्थन योजना (PSS) की भी खरीद हुई है। पिछले साल देश के उत्पादन का 17.8 प्रतिशत के हिसाब से रिकॉर्ड स्तर पर 4.5 मिलियन टन दालों को खरीदा गया था।

हालांकि, ऐसी खरीद की अपनी सीमाएं हैं, जो राजकोषीय और बाजार-संबंधी दोनों से संबंधित हैं। बड़े पैमाने पर खरीद से सरकारी एजेंसियों के साथ बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा होता है। बदले में, कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि निजी व्यापार इस विश्वास में खरीदना बंद कर देता है कि एजेंसियों के पास बाजार में इन्हें उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह किसानों को समर्थन देने के लिए सरकारी खरीद को आगे बढ़ाता है, जिससे एक दुष्चक्र की शुरूआत होती है। हमने इसे चावल और गेहूं में देखा है और अब अरहर, चना, मूंगफली और रेपसीड-सरसों में भी देखने को मिल रहा है।

स्पष्ट रूप से मूल्य समर्थन के लिए एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, विशेष रूप से आज के परिदृश्य में, जहां भारत ज्यादातर कृषि-वस्तुओं में अधिशेष निर्माता से अधिशेष उत्पादक के लिए स्थानांतरित हो गया है। वैकल्पिक तंत्र अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अपनाई गई क्षेत्र योजना हो सकता है।

यूके में, पाँच हेक्टेयर से अधिक के सभी किसानों को न केवल फसल की खेती के लिए, बल्कि यहां तक कि इमारतों के निर्माण या संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए उत्खनन और इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए भी अपनी भूमि के उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होता है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के पास क्षेत्रीकरण नियम हैं, जो फसल उत्पादन को घरेलू, औद्योगिक और निर्यात मांग के साथ संरेखित करते हैं। सब्सिडी भी विशेष फसलों के तहत परिभाषित क्षेत्रों को आवंटित करने वाले किसानों से जुड़ी हुई है।

भारत में, गन्ना नियंत्रण आदेश में वास्तव में उस फसल की मात्रा को ठीक करने का प्रावधान है, जो किसी भी उत्पादक को मिल को आपूर्ति करने के लिए खेती कर सकता है, जिसके लिए गन्ना क्षेत्र आरक्षित है। उत्पादक केवल गन्ने की आरक्षित मात्रा के लिए सरकारी अनिवार्य मूल्य का हकदार है। इस मॉडल, हालांकि गन्ने में कड़ाई से लागू नहीं है, को अन्य फसलों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

एफसीआई के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति ने वास्तव में अनाज की एमएसपी-आधारित खरीद को सीमित करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने व्यक्तिगत किसानों के लिए बिना किसी कैप के धान और गेहूं खरीदना जारी रखा। केवल PSS के तहत, MSP- आधारित खरीद का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दिन 25 क्विंटल प्रति किसान अधिकतम सीमा तय की गई। वर्तमान परिदृश्य में हमें वास्तव में एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है।

हर फसलों के मौसम से पहले विभिन्न कृषि उत्पादों की मांग का राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान लगाना संभव बनाना चाहिए। जिससे मांग, जो घरेलू खपत और वैश्विक निर्यात-आयात दोनों अनुमानों तक विस्तृत है, को प्रमुख उत्पादक राज्यों में उनके संबंधित पांचवर्षीय औसत

उत्पादन/ एकड़ स्तर के अनुपात में विभाजित किया जा सकेगा। राज्य क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर अपनी मांग आवंटन को उप-विभाजित कर सकते हैं।

मांग के अनुमानों के आधार पर, राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्र में बुवाई के मौसम से पहले अलग-अलग किसानों के क्षेत्र को विभिन्न फसलों के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। केवल ऐसे पंजीकृत क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें ही एमएसपी खरीद लाभ की हकदार हो सकती हैं। किसी भी अतिरिक्त उत्पादन को किसानों द्वारा बाजार की दरों पर बेचा जाना होगा।

फसलों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की योजना ने लोकतंत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन खुद किसान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लेखक द्वारा किए गए 2017 के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर विचार के लिए काफी खुले हुए हैं। वे अर्थशास्त्रियों की तुलना में आपूर्ति-मांग बेमेल से अधिक मूल्य अस्थिरता के संपर्क में हैं।

व्यक्तिगत फसलों के तहत क्षेत्र की योजना, आपूर्ति-मांग परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, न केवल अनुचित मूल्य की अस्थिरता की जांच करने में मद्द करेगी, बल्कि उर्वरक और पानी जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग को भी बढ़ावा देगी। गन्ने जैसी फसलों के लिए लगाए गए क्षेत्र को नियंत्रित करने का समय निश्चित रूप से आ गया है।

सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें इस वक्त क्षेत्र नियोजन कार्यान्वयन की आवश्यकता है, साथ ही वैसे किसान जिनके व्यक्तिगत क्षेत्र रोपण सीजन के आगे पंजीकृत हैं, उनके विचार को प्रचारित करना और खरीद/एमएसपी समर्थन का आश्वासन देना होगा। दूसरा, सरकार, शायद कृषि लागत और मूल्य आयोग को हर फसल के लिए घरेलू खपत, औद्योगिक और निर्यात मांग के विश्वसनीय पूर्वानुमान के साथ सामने आना चाहिए। तीसरा, सरकार को ऐसा बयान जारी करना बंद करना चाहिए कि हर साल हर फसल के उत्पादन में 5-10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो रही है। किसानों के लिए, उत्पादन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह ऐसी कीमतें हैं, जो वास्तव में अधिक मायने रखती हैं।

GS World टीम...

रायथू बंधु योजना

क्या है?

- तेलंगाना सरकार ने राज्य के किसानों के लिए रायथू बंधु योजना शुरू की है। इसे किसानों की निवेश सहायता योजना (FISS) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक कल्याणकारी योजना है, जो विशेष रूप से किसानों के लिए शुरूआत कर रही है।
- इस योजना में, राज्य सरकार किसानों को सालाना दो फसलों रबी और खरीफ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

- इस योजना की 10 मई, 2018 को शुरुआत की गयी है। हालांकि, इस योजना की घोषणा फरवरी, 2018 में हुई थी, लेकिन आखिरकार, इसे 10 मई, 2018 को शुरू किया गया है।
- राज्य सरकार ने इसके लिए 12,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

लाभ

- रायथू बंधु योजना के तहत कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए प्रति सीजन इस योजना के तहत, राज्य सरकार 4000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
- इस योजना के मुताबिक,रबी और खरीफ के मौसम के लिए सालाना दो बार यह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- विस्तार के अनुसार, लगभग 97% किसानों के पास प्रति व्यक्ति 10 एकड़ से भी कम भूमि है और कुल कृषि भूमि 1.42 करोड़ एकड़ है और राज्य में किसानों की संख्या 71.75 लाख है।
- किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज, उर्वरक, कीटनाशकों या किसी भी अन्य इनपुट आवश्यकता की खरीद के लिए सहायता का उपयोग कर सकते हैं।
- इस योजना में कृषि और बागवानी फसलें दोनों शामिल होंगी और सभी किसानों को उनके भूमि अधिग्रहण के आकार के बावजूद लाभ होगा।

एमएसपी क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी, 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों की संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है?
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है?
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है?
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है?
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति?

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए रायथू बंधु योजना प्रारम्भ किया।
2. रायथू बंधु से तात्पर्य 'किसानों का मित्र' है।
3. सीएसीपी के द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. 'रायथू योजना' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना की शुरुआत 10 मई, 2018 को की गई।
2. यह एक कल्याणकारी योजना है जो विशेष रूप से किसानों के लिए शुरु की गई है।
3. इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकार किसानों को सालाना दो फसलों (रबी व खरीफ) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
2. इस आयोग का गठन वित्त वर्ष 2017-18 में किया गया।
3. कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

1. Consider the following statements-

1. Recently Andhra Pradesh government has started Rythu Bandhu Scheme for farmers.
2. 'Rythu Bandhu' means 'friend of farmer'.
3. CACP releases minimum support price for 24 agriculture crops.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 (b) 1 and 2
(c) 2 and 3 (d) All of the above

2. Consider the following statements regarding Rythu Bandhu Scheme-

1. This scheme was started on May 10, 2018.
2. It is a welfare scheme which has been started especially for farmers.
3. Under this scheme, related state government provides financial support to farmers for two crops (Rabi and Kharif).

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 (b) 1 and 2
(c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

3. Consider the following statements regarding the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)-

1. It is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India.
2. This Commission was established in the financial year-2017-18.
3. The Commission was established with the aim of creating a balanced and integrated value structure of agricultural products.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 (b) 1 and 2
(c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'आजादी के बाद से कृषि संकट के समाधान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, किन्तु जमीनी स्तर पर कोई भी पूर्णरूप से सफल नहीं हो सकी।' इस सन्दर्भ में किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना, कृषि संकट के समाधान में कहाँ तक सहायक साबित होगी? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. 'Various schemes had been started after independence for the resolution of agriculture crisis but none were successful.' In this context, to what extent farmers' Investment support scheme will be helpful in the resolution of agriculture crisis? Discuss. (250 Words)

नोट : 16 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2. (d) होगा।